

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 243
No. 3] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933 [N.C.T.D. No. 243

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

सं. फा. 12(15)/वित्त (राज.-1) 2011-12/डीएस III/33.—दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 06) द्वारा यथा संशोधित दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2 सितम्बर, 2011 से 12 सितम्बर, 2011 के दौरान 2 सितम्बर 2011 को प्रवेश करने की सूचना और 12 सितम्बर 2011 को प्रस्थान करने की सूचना सहित होटलों में उपलब्ध सुख सुविधाओं पर विलासिता कर के भुगतान से निम्नलिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को इसके द्वारा भुगतान में छूट प्रदान करते हैं।

6 सितम्बर से 9 सितम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अयोजित पेसीफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट के प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदार, इसके बाद 10-12 सितम्बर, 2011 को पीएटीए निदेशक मंडल की बैठक।

छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है :—

1. विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पेसीफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन

ट्रेवल मार्ट, 2011 के प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों के होटलवार, कक्षवार, ठहरने की अवधि, कमरे की टाइप और होटल द्वारा वसूल किए गए शुल्क की सूची उपलब्ध कराएगा।

2. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार संबंधित होटलों को प्रमाण-पत्र सहित पेसीफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पीएटीए) ट्रेवल मार्ट, 2011 होटलवार, कमरावार ठहरने की अवधि, कमरे का टाइप और शुल्क इसे अधिसूचना द्वारा छूट के लिये हकदार प्रतिनिधियों/अतिथियों/भागीदारों को सूची जारी करेगा।

3. संबंधित होटल बारी-बारी से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पूर्वोक्त सूची के साथ प्रमाण-पत्र, सितम्बर, 2011 के माह के लिये फार्म 8 में उनकी विलासिता कर विवरणियों सहित होटलों द्वारा दिए गए बिलों की प्रतियां संलग्न करेंगे। इस अधिसूचना के आधार पर विलासिता कर के भुगतान से छूट का दावा करते समय सितम्बर, 2011 के माह के लिये दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 के अंतर्गत यथानिर्धारित फार्म 8 के कॉलम 1 (ख) में पेसीफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पीएटीए) ट्रेवल मार्ट, 2011 में भाग लेने वाले अतिथियों/प्रतिनिधियों/भागीदारी को उपलब्ध आवास संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेन्द्र कुमार कामरा, उप-सचिव-III

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th January, 2012

No. F. 12(15)/Fin.(Rev.-I)/2011-12/DS III/33.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), as amended by the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2000 (Delhi Act 6 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby exempt the following persons or class of persons from payment of Luxury Tax on the Luxury provided in the Hotels during 2nd September, 2011 to 12th September, 2011 with check in on the 2nd September, 2011 and check out on the 12th September, 2011 (ten days) in the National Capital Territory of Delhi, namely:—

Delegates/Guests/Participants of the Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart, 2011, organized in New Delhi during 6th—9th September, 2011 followed by the PATA Board of Directors' Meeting from 10th—12th September, 2011 by the Ministry of Tourism, Government of India.

The exemption is granted subject to the following conditions:—

1. The Ministry of Tourism, Government of India shall provide to the Department of Luxury Tax, Government of National Capital Territory of Delhi the list of delegates/guests/participants for the Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart, 2011 hotel-wise and room-wise, furnishing there with the details about duration of stay, type of room and tariff charged by the hotel.
2. The Ministry of Tourism, Government of India shall issue certificates to the respective hotels along with the list of Delegates/Guests/Participants for the Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart, 2011 hotel-wise and room-wise, furnishing therewith the details about duration of stay, type of room and tariff entitled for exemption by this notification.
3. The respective hotels in turn shall enclose the certificates along with the aforesaid list issued by the Ministry of Tourism, Government of India and the copies of the bills raised by the hotels with their Luxury Tax Returns in Form -8 for the month of September, 2011. The respective hotels shall also furnish the turnover on accommodation provided to the Guests/Delegates/Participants attending the Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart, 2011 in column 1(B) of Form-8 as prescribed under Delhi Tax on Luxuries Rules.

1996 for the month of September, 2011 while claiming exemption from payment of Luxury Tax on the basis of the notification.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

S. K. KAMRA, Dy. Secy.-III

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

फा. सं. 21(02)/2012/एल ए एस.-IV/लेग/395.—निम्नलिखित अधिसूचना जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है:

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

विधेयक संख्या (02) 2012

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 11 जनवरी, 2012 को पुरःस्थापित किया गया)

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:—

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है।

(3) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। परन्तु इसमें इस अधिनियम की धारा 7 शामिल नहीं है जो 1 अप्रैल 2005 से लागू मानी जायेगी।

2. धारा 2 का संशोधन.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (जैड एल) में "शामिल" शब्द के स्थान पर "छोड़कर" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. धारा 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 4 में—

(क) "अठाईस" शब्द के स्थान पर "इक्कीस" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) परन्तुक में संख्या "28" के स्थान पर "21" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. धारा 28 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 28 में—

(क) उप-धारा (1) में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्दों को प्रस्थापित किया जायेगा;

(ख) उप-धारा (2) में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. धारा 29 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 29 में दूसरे स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 3.—इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 21) की धारा 2 की उप-धारा के खंड (पी) के अन्तर्गत यथापरिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर वाली रिटर्न को ऐसा ही माना जायेगा जैसा इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हस्ताक्षर किये गये हैं।

6. धारा 74 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (10) में "सात" शब्द के स्थान पर "आठ" शब्द को प्रस्थापित किया जायेगा।

7. धारा 81 का संशोधन.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 81 की उप-धारा (2) में खंड (क) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"आगे उपबंध है कि उक्त परन्तुक को 01 अप्रैल 2005 से लागू होना माना जायेगा।"

8. धारा 106 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 106 में उप-धारा (3) पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा को जोड़ा जायेगा, और इसे 01 अप्रैल 2005 को जोड़ा गया माना जायेगा अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में कुछ भी होते हुए, 01 अप्रैल, 2005 से पहले समाप्त अवधि के विषय में वसूली, निर्धारण अनुमानित निर्धारण, पुनः निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा, शुद्धीकरण, संदर्भ, पंजीकरण, संग्रह जमा वापसी या जमा कर छूट के लाभ की अनुमति या कर को आगे बढ़ाने, कोई अर्थदंड लगाने या ब्याज या किसी राशि को जब्त करने या कोई भी अन्य उद्देश्य जो उपरोक्त उद्देश्यों से संबंधित या प्रासंगिक हो या न हो तथा या ऐसी कार्यवाहियों के विषय में कर अर्थदंड, ब्याज या जब्त राशि यदि कोई है, ऐसी कार्यवाहियों के कारण जिसका भुगतान 01 अप्रैल, 2005 से पहले किया गया है, निरस्त अधिनियम तथा 01 अप्रैल, 2005 से तत्काल पहले लागू इसके अन्तर्गत जारी सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं फार्म तथा नोटिस का ऐसा ही प्रभाव रहेगा जैसे अधिनियम पारित न किया गया हो।"

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

धारा 2 में खरीद और बिक्री टर्नओवर की परिभाषा में एकरूपता लाने के लिये खरीद टर्न ओवर की परिभाषा में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

कर नियोजन को सरल बनाने और इसे अधिक सक्षम बनाने के लिये शुद्ध करके भुगतान के लिये धारा 3 का संशोधन करके समय 28 दिन से घटाकर 21 दिन किया जाना प्रस्तावित है।

विवरणी में त्रुटियों के सुधार के लिये विवरणियों के संशोधन और आपत्ति प्रस्तुत करने की समय सीमा 4 वर्ष से घटाकर एक वर्ष के लिये धारा 28 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (थ) के उपबंधों के अनुसार डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित हुई किसी विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक विवरणी के समान मानने हेतु व्यवस्था करने के लिये अधिनियम की धारा 29 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (10) के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा और एक वर्ष बढ़ाना, जिसका तात्पर्य यह है कि ये अपीलें 31-3-2012 तक निर्णित करने के स्थान पर 31-3-2013 तक निर्णित की जानी होंगी जिसके लिये धारा 74 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अपीलें दायर करने में विलम्ब को माफ करने के लिये उच्च न्यायालय को शक्ति सौंपने के लिये 2010 के दिल्ली अधिनियम 12 के माध्यम से धारा 81 में एक परन्तुक का सन्निविष्ट किया गया था, जो 01 फरवरी, 2011 से प्रभावी हुआ जबकि संशोधन का अभीष्ट प्रयोजन कुछ उन अपीलों पर प्रावधान लागू किया जाना था जो संशोधन से पूर्व विलम्ब से दायर करने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी, शीघ्रतापूर्वक संशोधन से इसका केवल उपयोगी, प्रयोजन/उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि संशोधन पूर्व प्रभाव से प्रभावी होता है जो धारा 81 में प्रस्तावित संशोधन से किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा था।

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत संशोधन करने की शक्ति के संबंध में किसी विशेष बचाव खंड की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 106 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के सुझाव पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है।

नई दिल्ली :

(शीला दीक्षित)

दिनांक :

मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 केन्द्रीय सरकार से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से नये पदों के लिये किसी राशि की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 किसी अधिकारी को अधीस्थ विधायी शक्तियां सौंपने के लिये प्रावधान नहीं करता है।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th January, 2012

No. 21(02)/2012/LAS-IV/Leg/395.—The following Notification is Published for General Information :

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012

(Bill No. 02 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th January, 2012)

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, except Section 7 of this Act which shall be deemed to come into force with effect from 1st April, 2005.

2. Amendment of Section 2.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2, in sub-section (1), in clause (zl), for the word “including”, the word “excluding” shall be substituted.

3. Amendment of Section 3.—In the principal Act, in section 3, in sub-section (4),—

(a) for the words “twenty eight”, the words “twenty one” shall be substituted;

(b) in the proviso, for the number “28”, the number “21” shall be substituted.

4. Amendment of section 28.—In the principal Act, in section 28,—

(a) in sub-section (1), for the words “four years”, the words “one year” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words “four years”, the words “one year” shall be substituted.

5. Amendment of Section 29.—In the principal Act, in Section 29, after the second Explanation, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“**Explanation 3.**—For the purposes of this Act, any return having digital signature as defined under clause (p)

of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), shall be treated as if the return has been signed as required under this Act”.

6. Amendment of Section 74.—In the principal Act, in section 74, in sub-section (10), for the word “seven”, the word “eight” shall be substituted.

7. Amendment of Section 81.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), in Section 81, in sub-section (2), after the proviso to clause (a), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the above proviso shall be deemed to have come into force with effect from the First day of April, 2005.”

8. Amendment of Section 166.—In the principal Act, in section 106, after sub-section (3), the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the First day of April, 2005, namely :—

“(4) Notwithstanding anything contained in this Act, for the purpose of the levy, assessment, deemed assessment, reassessment, appeal, revision, review, rectification, reference, registration, collection, refund or input or credit of input tax, of allowing benefit of exemption or deferment of tax, imposition of any penalty or of interest or forfeiture of any sum, which relates to any period ending before 1st day of April, 2005 or for any other purpose whatsoever connected with or incidental to any of the purposes aforesaid, and whether or not the tax, penalty, interest or sum forfeited, if any, in relation to such proceedings, is paid before, on or after 1st day of April, 2005, the repealed Act and all rules, regulations, orders, notifications, forms and notices issued thereunder and in force immediately before 1st day of April, 2005 shall continue to have effect as if this Act has not been passed.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To bring uniformity in the definition of purchase and sale turnover in Section 2, the definition of purchase turnover is proposed to be amended.

To smoothen the tax planning and make it more efficient, time for payment of Net Tax is proposed to be reduced from 28 days to 21 days by amending Section 3.

To reduce the limitation period for revision of returns and filing of objection for correction of deficiencies in return from four years to one year, Section 28 is proposed to be amended.

To provide for treating any return having been digitally signed as per the provisions of clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) at par with electronic return to mean returns in the Act 29 is proposed to be amended.

To further extend the period of limitation prescribed under sub-section (10) of Section 74 of the DVAT Act by

another year, which would mean that these appeals would have to be decided by 31-3-2013 instead of 31-3-2012, Section 74 is proposed to be amended.

For conferring power on the High Court to condone the delay in filing of appeals, a proviso was inserted in the Section 81 through the Delhi Act 12 of 2010 which took effect from 1st February, 2011. While the intended purpose of the amendment was to make the provision applicable to some appeals which were dismissed by the High Court for delayed filing, before the amendment, the earlier amendment can achieve its useful purpose/objective only if the amendment is given effect retrospectively, which is being attempted through the proposed amendment in Section 81.

To provide for a specific saving clause in respect of the power of revision under the Delhi Sales Tax Act, 1975, Section 106 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to be amended on the suggestion of the Additional Solicitor General of India.

The Bills seek to achieve the aforesaid objectives.

New Delhi:

Dated:

(SHEILA DIKSHIT)

Chief Minister/Minister of Finance

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

फा. सं. 21(01)/2012/एलएस-IV/लेग/396.—
निम्नलिखित अधिसूचना जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है:

दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2011

विधेयक संख्या (01) 2012

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 11 जनवरी, 2012 को पुरःस्थापित किया गया)

दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम, 03) का पुनः संशोधन करने के लिये

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर विस्तारित है।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. धारा 25 का संशोधन.—दिल्ली सरकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम, 3) (इसके बाद "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित की धारा 25 के परंतुक के खंड (ग) में निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) उपबंध है कि जहां सरकार सहकारी समिति का सदस्य है, सरकार द्वारा समिति में नामित प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होगा :

शर्त यह है कि जहां सरकार ने सहकारी समिति की शेयर पूंजी में अंशदान किया है, वहां सरकारी प्रतिनिधि का मत अधिकार सहकारी समिति की अंशपूंजी में सरकार के भाग के अनुपात में होगा जिसका वितरण मनोनीत सदस्यों में बराबर-बराबर किया जायेगा;"

3. धारा 35 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (10) में खंड (ग ग) के लिये निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"(ग ग) जहां सरकार द्वारा रखी गई अंशपूंजी जारी अंशपूंजी की कुल राशि कुल जारी अंशपूंजी का साठ प्रतिशत या अधिक है, या सरकार ने सहकारी समिति को ऋण दिया है या अग्रिम राशि दी है या मूलधन या सहकारी समिति द्वारा जारी डिबेंचरों या बॉण्डों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी है या समिति के मूलधन या ऋण तथा अग्रिम राशि पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी है जो समिति द्वारा उधार ली गई कुल राशि के साठ प्रतिशत से कम नहीं है अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यों को मनोनयन निम्न प्रकार से होगा अर्थात् :—

सरकार के पास सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों का प्रतिशत

साठ से सत्तर प्रतिशत सत्तर प्रतिशत;

सत्तर से अस्सी प्रतिशत सत्तर प्रतिशत;

अस्सी से नब्बे प्रतिशत अस्सी प्रतिशत;

नब्बे प्रतिशत से अधिक सौ प्रतिशत :

उपबंध है कि इस खंड के अन्तर्गत एक बार प्राप्त अधिकार तब तक जारी रहेगा, जब तक अंशपूंजी या ऋण गारंटी का प्रतिशत साठ प्रतिशत से नीचे नहीं जाता है;"।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

यह पया गया है कि 31-3-2011 को दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की कुल जारी तथा अभिदत्त पूंजी 3,142.13 लाख रुपये है जिसमें से 3,026.00 लाख रुपये सरकार ने दिये हैं तथा 116.13 लाख रुपये दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की सदस्य सहकारी समितियों ने दिये हैं जो क्रमशः 96.30 प्रतिशत तथा 3.70 प्रतिशत है।

92 DG/12-2

दिल्ली सरकार की शेयर पूंजी 64.00 लाख रुपये के बढ़कर 3026.00 लाख रुपये हो गई है जबकि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की सदस्य समितियों की शेयर पूंजी 72.93 लाख रुपये से बढ़कर 117.59 लाख रुपये हो गयी है।

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड में 96.30 प्रतिशत शेयर पूंजी होने के कारण सरकार को कुल 11 निदेशकों में से केवल 8 के मनोनयन का अधिकार है।

3.70 प्रतिशत के छोटे से हिस्से के अनुसार सदस्य समितियों को तीन सदस्य चुनने का अधिकार है और महानिकाय में उनके मतों की संख्या 1276 है क्योंकि 31-3-2011 को दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की सदस्य समितियों की संख्या 1276 है।

इस प्रकार सरकार द्वारा मनोनीत किये गये निदेशकों की संख्या तथा एक मत एक समिति की तुलना में निदेशकों के मत को पुनः विनियोजित किये जाने की आवश्यकता है।

विधयेक का यह उद्देश्य है।

हारून यूसुफ, सहकारिता मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2011 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से पर्याप्त व्यय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं करता है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

दिल्ली सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2011 किसी पदाधिकारियों पर विधायी शक्ति सौंपने की मांग नहीं करता है।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

F.No. 21/(01)/2012/LAS-IV/Leg./396.—The following Notification is published for general information :

The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2011.

Bill No. 01 of 2012

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th January, 2012)

A

BILL

further to amend the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 25.—In the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) (hereinafter referred to as “the principal Act”), in the proviso to Section 25, for clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(c) where the Government is a member of the Co-operative Society, each person nominated by the Government on the committee shall have one vote :—

Provided that where the Government has subscribed to the share capital of such Co-operative Society, the voting rights of the Government nominees shall be in proportion to the share of the Government in the paid up equity of the Co-operative Society which shall be distributed among the nominated members equally;”

3. Amendment of Section 35.—In the principal Act, in Section 35, in sub-section (10), for clause (cc), the following clause shall be substituted, namely :—

“(cc) where the total amount of issued equity share capital held by the Government is sixty per cent or more of the total issued share capital or the Government has given loan or made advances to the Co-operative Society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures or bonds issued by the Co-operative Society or guaranteed the payment of principal and payment of interest on loan and advances to the Co-operative Society in amount not less than sixty per cent in the aggregate of the total amount so borrowed by the Co-operative Society, members of the committee including the Chairman in the following manner, namely :—

“Percentage held by Government	Percentage of members of the committee to be nominated by the Government
Sixty to seventy per cent	Seventy per cent;
Seventy to eighty per cent	Eighty per cent;
Eighty to ninety per cent	Ninety per cent;
Above ninety per cent	Hundred per cent :

Provided that the right once accrued under this clause shall continue until the percentage of the amount in respect of share contribution or guaranteed loan goes down to less than sixty per cent.”

Statement of Objects and Reasons

It has been observed that as on 31-3-2011, the total issued and subscribed capital of the Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. (DCHFC) is Rs 3,142.13 lakh out of which Rs. 3,026.00 lakh is subscribed by the Government and Rs. 116.13 lakh is subscribed by the member Co-operative Societies of Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. which comes to 96.30% and 3.70% respectively.

The share capital of the Government of NCT of Delhi has gone up from Rs. 64.00 lakh to Rs. 3026.00 lakh whereas the share capital of the member societies of Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. has gone up from 72.93 lakh to Rs. 117.59. lakh.

As per the provisions of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003, with 96.30% holding in the Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. the Government is entitled to nominate only eight directors out of total strength of eleven directors.

However, with minor stake of 3.70%, the member societies are entitled to elect three members and are having 1276 votes in the General Body since number of member societies of Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Ltd. as on 31-3-2011 is 1276.

There is thus a need for re-appropriation of number of Directors nominated by the Government and the value of the vote of Directors as compared to the one vote per society.

Hence, this bill.

(HAROON YUSUF)

Minister of Co-operation

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2011 does not involve any additional financial assistance from the Central Government through substantive expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2011 I does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

P. N. MISHRA, Secy.